भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1775

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

रोजगार सृजन

1775. श्री नवसकनी के.:

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सृजित नौकरियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत विशेषकर तमिलनाडु में कितने युवाओं को रोजगार मिला है;

(ग) प्रत्येक राज्य में रोजगार सृजन में योगदान देने वाले प्रमुख उद्योग कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा तथा निजी क्षेत्र में राज्य-वार कुल कितने रोजगार सृजित किए गए;

(च) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं; और

(छ) निजी क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका

मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

तमिलनाडु राज्य में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या (युवाओं सहित) अनुबंध-I में दी गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 28.02.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 4.7 करोड़ से अधिक रिक्तियां (जिसमें अन्य के साथ-साथ सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं) जुटाई गई हैं।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला (सरकारी और निजी क्षेत्र सहित) अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), वर्ष 2019-20 में 50.9% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया।

15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) https://www.mospi.gov.in/download-reports पर देखा जा सकता है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्य स्थिति के आधार पर कामगारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित वितरण प्रतिशतता https://www.mospi.gov.in/download-reports पर देखी जा सकती है।

*****

अनुबंध-।

लोक सभा के दिनांक 10.03.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1775 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य में केंद्रीय योजनाओं का रोजगार सृजन/लाभार्थी

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	तमिलनाडु
1	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) (लाभार्थी संख्या) [2020-21 से 2023-24]	8.05 लाख (दिनांक 31.03.2024 तक)
2	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (ऋण खातों की संख्या)) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24]	319.01 लाख (दिनांक 01.11.2024 तक)
3	प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) (लाभार्थियों की संख्या) [वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25]	5.23 लाख (दिनांक 08.07.2024 तक)
4	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (अनुमानित सृजित रोजगार की संख्या) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25]	2.56 लाख (दिनांक 29.01.2024 तक)
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) (सृजित मानव दिवसों की संख्या) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24]	167.15 करोड़
6	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) [वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25]	27857 (दिसंबर, 2024 तक)
7	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) [2019-20 से 2024-25]	1.10 lakh (दिसंबर, 2024 तक)
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) (कुशल प्रशिक्षित नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या) [2019-20 से 2023-24]	37074

स्रोत: संबंधित मंत्रालय